लोकतंत्र की अखंड धारा, विश्व सुदृढ़ संगठन हमारा

दीपकमल संदेश

दीपकमल संदेश मासिक पत्रिका

वर्ष 11 | अंक 73 | मई 2026 | हिमाचल प्रदेश

बंगाल में नया सवेरा

विधानसभा चुनाव परिणाम 2026

बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में ऐतिहासिक विजय

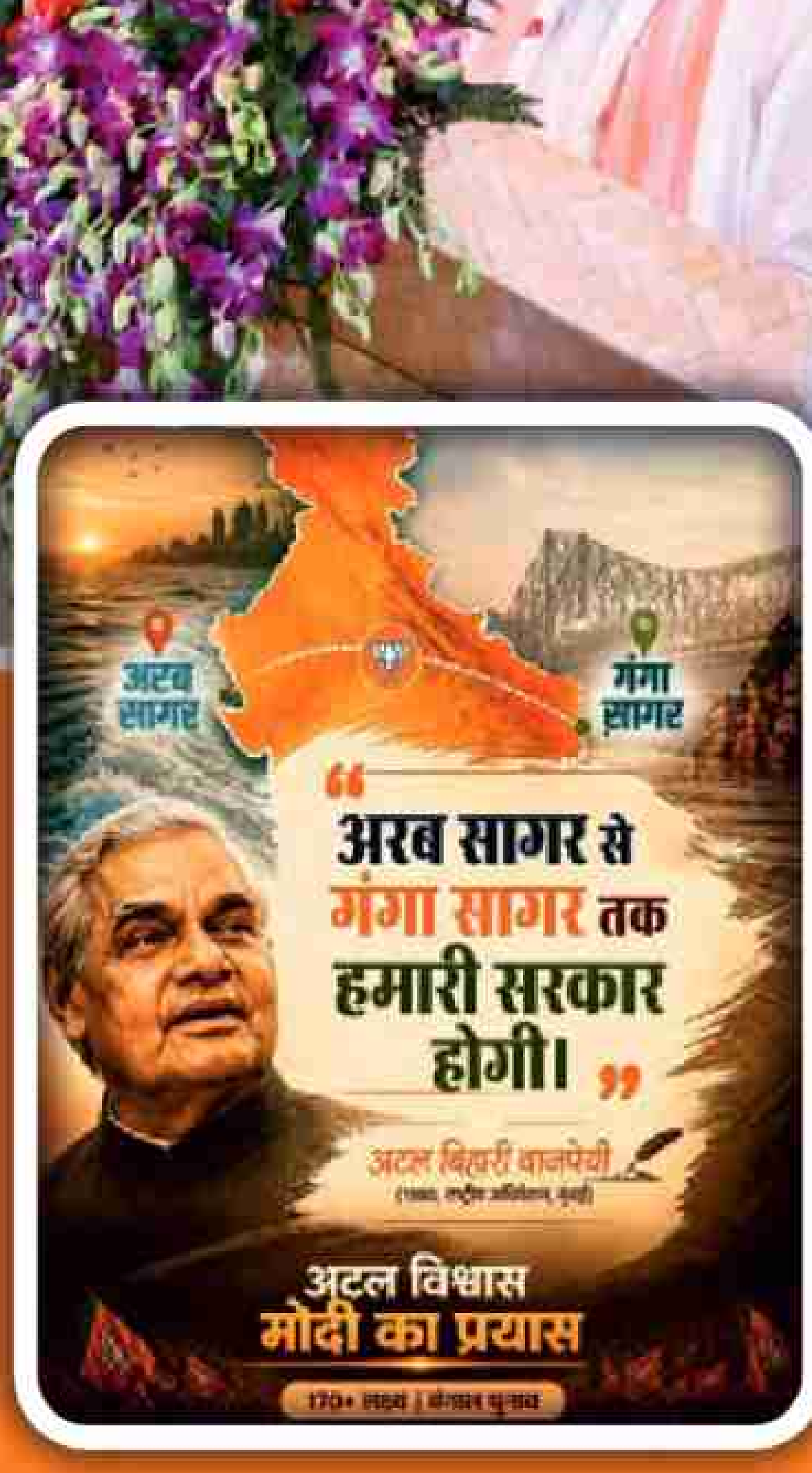

बंगाल में श्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मरण किया और उनकी भूमि पर उनके सपनों का बंगाल बनाने का संकल्प लिया।

इसी संकल्प की कड़ी में पीएम मोदी ने शपथ समारोह में श्री माखनलाल सरकार जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया... जिन्होंने डॉ. मुखर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जम्मू-कश्मीर में उनके साथ गिरफ्तार हुए और जीवन भर बंगाल में पार्टी की जड़ें मजबूत करते रहे।

यह क्षण केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन अनगिनत समर्पित कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण इस विचार के लिए समर्पित कर दिया।

दीपकमल सन्देश

मुख्य संपादक
गणेश दत्त

व्यवस्थापक
त्रिलोक जम्बाल

संपादक मंडल
डॉ. चमन लाल गुप्त
डॉ. सिकन्दर कुमार

डिजाईन एवं कॉन्सेप्ट
विवेकदीप शर्मा
9418853100,

सदस्यता शुल्क
त्रिवार्षिक 400

सम्पर्क
0177– 2633440, 2831892, 2831893
deepkamalsandesh@gmail.com

फैक्स:
0177–2832677

प्रकाशक एवं मुद्रक
गणेश दत्त द्वारा दीपकमल सन्देश न्यास के लिए दीपकमल भवन, टॉप फ्लोर, कामनानगर चक्कर, शिमला–5, हि0 प्र0, से प्रकाशित एवं डॉलफिन प्रिन्टोग्राफिक्स, झण्डेवाला, एक्सटैन्शन, न्यू दिल्ली से मुद्रित।

विषय सूची

संपादकीय ... 2

विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता - नरेन्द्र मोदी ... 3

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व चमत्कार अब विश्वभर में ... 5

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत सुक्खू सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और माफिया राज पर जनता का करारा प्रहार : जयराम ठाकुर ... 7

नगर परिषदों की 229 सीटों में भाजपा ने 120 सीटें जीतकर प्रदेश में बनाया नया राजनीतिक इतिहास ... 8

मोदी-शाह के चक्रव्यू से ममता बाहर नहीं निकल सकी ... 9

संघ का कार्य हिन्दू समाज को संगठित, सशक्त एवं समर्थ बनाने के लिए चल रहा है ... 10

हम महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे : नरेन्द्र मोदी ... 11

कार्यकर्ताओं के तप से भाजपा आज देश की सबसे भरोसेमंद पार्टी बनी है : नरेन्द्र मोदी ... 13

नक्सल-मुक्त भारत मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक : अमित शाह ... 14

विपक्षी गठबंधन ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया : अमित शाह ... 16

कांग्रेस के नेतृत्व वाले महिला विरोधी गठबंधन ने देश की आधी आबादी के साथ घोर विश्वासघात किया है : नितिन नवीन ... 18

किसानों, युवाओं, भारत-न्यूजीलैण्ड एफटीए : नौकरियों और विास के लिए मलिाओं के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक समझौता ... 19

रेल पटरियों का आधुनिकीकरण ... 20

भारत की औषधि रणनीति : पैमाने से नवाचार की ओर ... 21

भाजपा के वरिष्ठ नेता बलबीर पुंज नहीं रहे ... 22

बाबासाहेब के विचार, नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व और 'विकसित भारत' का संकल्प ... 23

सम्पादकीय

राहुल गांधी असभ्य-असंस्कारित धूर्त और राष्ट्र विरोधी-अराजक दिमाग

भारत में शायद राहुल गांधी पहला नेता होगा जो असभ्य भी है असंस्कारित भी है और राष्ट्र का अपमान करने में सबसे ऊपर है। वैसे तो समय–समय में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री विरोधी देश विरोधी बयान आते रहते हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस को राहुल गांधी के बयानों का खमियाजा भुगताना पड़ता है, अधिकतर लोग तो यह कहते रहते हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सपोर्टर है जो समय–समय पर भाजपा की मदद करता रहता है।

अभी हाल ही में राहुल गांधी का एक बयान आया जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश प्रवास पर गये हुए थे, उनका बयान आया प्रधानमंत्री गद्दार हैं, गृहमंत्री गद्दार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गद्दार है, सभी देशवासी हैरान परेशान थे कि आखिर राहुल बाबा ने ऐसा बयान क्यों दिया, मांग उठने लगी कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं संवैधानिक पद पर बैठे हैं कैबिनेट रैंक से सुशोभित हैं, लेकिन उनकी समझ और बाणी गली छाप बिगड़े बालक की तरह है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए शायद राहुल जरूरी है क्योंकि उसने कांग्रेस को समाप्त करने का संकल्प लिया हुआ है।

राहुल गांधी कांग्रेस की बहुत बड़ी पूंजी है जो लगातार 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, सेना के शौर्य पराक्रम में विश्वास नहीं, चोरी छिपे भारत विरोधियों से मिलकर देश की छवि खराब करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है।

राहुल के खिलाफ कई स्थानों में केस दर्ज हुये हैं समय आने पर उनका निपटारा होगा, लेकिन यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि किसी बरिष्ठ कनिष्ठ कांग्रेसी ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, स्पष्ट है कि कांग्रेस की यह सोची–समझी योजना है कि प्रधानमंत्री की बेइज्जती करो, गृहमंत्री का अपमान करो, देश भक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान करो, कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा दी, विपक्ष खासकर कांग्रेस देश को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री को भला–बुरा कह रहा है, गृहमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर मंच से कोसने का सिलसिला गत् कई वर्षों से चला आ रहा है, देश की जनता देखती आ रही है, देश की जनता कांग्रेस को उसकी औकात बताती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है।

कांग्रेस ने कभी भी सेना का सम्मान नहीं किया, औपरेशन सिन्दूर का समर्थन नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन नहीं किया, राहुल विदेशों में बिना बताये जाकर चोरी छिपे देश को बदनाम करते आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल की कुल आय 64 करोड़ है और वह विदेशी दौरों पर 125 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हैं, अब वह खुद ही बताये कि गद्दार कौन है? देश राहुल गांधी से पूछता है, समय आने पर उत्तर तो देना होगा। अन्यथा जेल की रोटी खाने से कौन रोक सकता है।

राहुल गांधी को देश की मर्यादा का ध्यान रखना होगा, विदेशी धरती पर देश का अपमान कोई सहन नहीं करेगा और कांग्रेस और राहुल की एक–एक देश–समाज सरकार के मुखिया का अपमान का उसे ईनाम अवश्य मिलेगा। ■

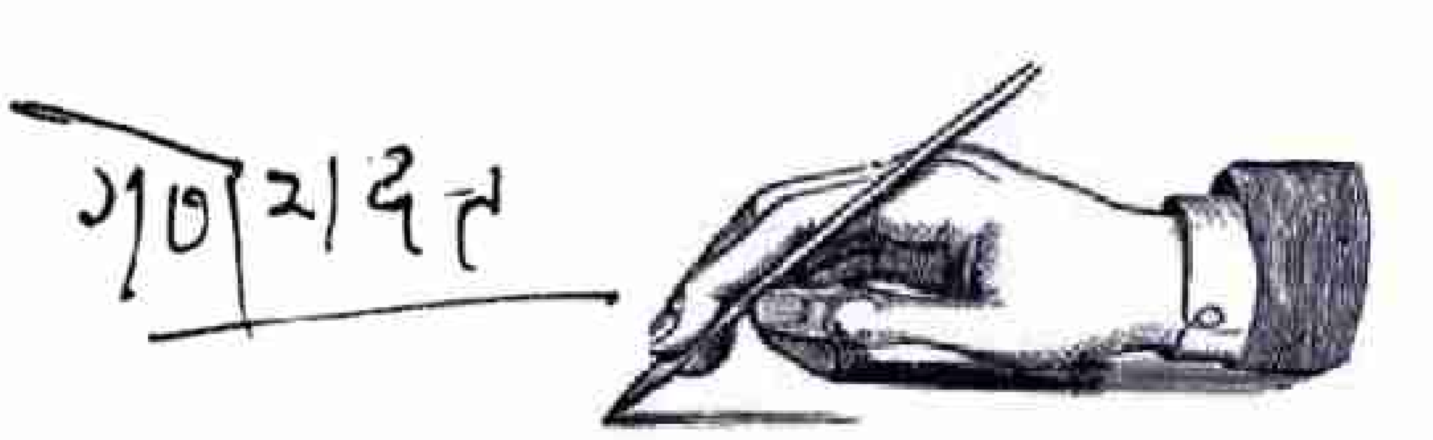

विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता - नरेन्द्र मोदी

By Erik Solheim, DN

पश्चिमी देशों के नेताओं को नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण पर लगातार दिए जाने वाले जोर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।

दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 18 मई को नॉर्वे की यात्रा पर जाएंगे। यहाँ झ्पदह भ्तंसक उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान भारतीय व्यापारों को बढ़ावा देंगे, वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे और भारत–नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों को मोदी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

जहां नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की लोकप्रियता अपने देश में मुश्किल से 30 प्रतिशत तक है, वहीं मोदी की लोकप्रियता करीब 70 प्रतिशत है। दुनिया के किसी बड़े देश का नेता अपने देश में मोदी जितना लोकप्रिय नहीं है।

मोदी पिछले 12 साल से ज्यादा समय से भारत की सत्ता में हैं। अगर वह फिर चुनाव लड़ते हैं, तो सभी संकेत बताते हैं कि उन्हें फिर से जीत हासिल हो सकती है। यूरोप के नेताओं के लिए यह केवल एक सपने जैसा है। उनकी सफलता के पीछे तेज आर्थिक विकास, मजबूत विचारधारा, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और उनकी निजी जीवन यात्रा का बड़ा योगदान है।

मोदी की पृष्ठभूमि दुनिया के ज्यादातर नेताओं से बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकतर राष्ट्राध्यक्ष उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं, लेकिन मोदी का बचपन बहुत साधारण था। उनके माता–पिता गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। यह कस्बा इतना छोटा है कि भारत में भी मुश्किल से कुछ ही लोग इसका नाम जानते थे। मोदी आज जहां हैं, वहां तक अपने खुद के बलबूते पर पहुंचे हैं और इसमें हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा है। वह नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री म्पदंत ळमतींतकेमद की तरह हैं – खुद सीखने वाले और मजबूत संगठनकर्ता।

मोदी ऐसे समय में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस विकास में उनका स्वयं का भी बड़ा योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 7 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है जोकि चीन से भी तेज है और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से काफी आगे है।

हालांकि विकास हर जगह समान नहीं है। भारत के अमीर और गरीब राज्यों के बीच बड़ा अंतर है। भारत के पास चीन जैसी बहुत बड़ी शिक्षित ूवतावितबम नहीं है। यहां अब भी नौकरशाही ज्यादा है और भारत अभी तक वैश्विक बाजार में निर्यात के लिए कोई प्रमुख उद्योग विकसित नहीं कर पाया है। लेकिन अगर विकास की यह दर बनी रही, तो 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था चार गुना हो जाएगी। तब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और अमेरिका को चुनौती देगा।

मैं भारत के लगभग हर राज्य में गया हूं और हर जगह विकास के संकेत दिखाई देते हैं। नए और आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं। दूर–दराज के इलाकों तक अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है और आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर–विंड–हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है।

मोदी हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ के सबसे बड़े समर्थक हैं। भारत आज दुनिया में सौर और पवन ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। पिछले साल भारत में कोयले से होने वाला प्रदूषण पहली बार कम हुआ।

पश्चिमी देशों के नेता मोदी द्वारा लगातार दिए जाने वाले पर्यावरण संदेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कई सम्मेलनों में गया हूं जहां मोदी मुख्य वक्ता रहे हैं। मोदी लगभग कभी जलवायु समझौतों या उत्सर्जन की बात नहीं करते। वह लोगों से पर्यावरण बचाने के लिए त्याग करने की अपील भी नहीं करते। उनका संदेश साफ होता है कि भारत 1.5 अरब लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है और यह काम ग्रीन ग्रोथ के जरिए किया जा सकता है। अब अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं है।

अगर अगला चुनाव धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जीत भी जाएं, तब भी भारत की मुख्य विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद ही रहेगी। हिंदू राष्ट्रवाद उस सवाल का भारत का जवाब है जिसका सामना औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग हर गैर–पश्चिमी देश ने किया। सवाल यह था कि आधुनिक कैसे बनें, लेकिन पूरी तरह पश्चिम जैसा बने बिना। इस रास्ते को सबसे पहले जापान ने अपनाया। जापान आधुनिक भी बना और अपनी संस्कृति से भी जुड़ा रहा। आज दक्षिण कोरिया जापान से ज्यादा अमीर है और अपनी संस्कृति व संगीत को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। चीन भी अपनी आधुनिकता को कन्फ्यूशियस विचारधारा, ताओवाद और बौद्ध धर्म जैसी अपनी परंपराओं से जोड़ता है।

भारतीय जनता पार्टी (ठश्रच) इस समय दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। उत्तर और मध्य भारत के हर क्षेत्र में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मौजूद हैं। भाजपा ने भारत में एक अनोखी सफलता हासिल की है। उसे ऊंची जातियों, पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों से एक समान समर्थन मिलता है। पार्टी को भारत के अरबपतियों का भी समर्थन है और दूरदराज के आदिवासी इलाकों का भी।

पश्चिमी देशों के कई विश्लेषक भाजपा की आलोचना करते रहते हैं। आलोचक एक बात उचित कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं को एकजुट करने की बात करती है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रमाण नहीं है कि भाजपा के शासनकाल में हिंदू–मुस्लिम संघर्ष बढ़े हों। कांग्रेस के समय ज्यादा हिंसा और दंगे हुए थे। पड़ोसी देशों से लाखों मुसलमान भारत आ रहे हैं, जबकि बहुत कम मुसलमान भारत छोड़कर जा रहे हैं।

लेकिन भाजपा का यह कहना कि इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशी धर्म हैं, और मुस्लिम आक्रमणों को ब्रिटिश शासन के बराबर मानना, कई मुसलमानों में असुरक्षा पैदा करता है। भाजपा के कई सुझाव सामान्य समझ वाले लगते हैं। जैसे कि यह विचार कि कोई अलग विवाह कानून नहीं होना चाहिए जिसके तहत मुस्लिम पुरुष अन्य पुरुषों की तुलना में अधिक आसानी से तलाक ले सकें। लेकिन एक नए और मजबूत हिंदू पहचान वाले भारत के निर्माण में असली परीक्षा यह होगी कि क्या भाजपा दुनिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय– भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को भी साथ लेकर चल पाती है।

भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा और गरीब पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने लोकतंत्र का रास्ता चुना। इसका श्रेय ब्रिटिश शासन को नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता, तो पाकिस्तान, म्यांमार और खाड़ी देशों में भी लोकतंत्र होता। भारत लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है।

आज की दुनिया में नॉर्वे जैसे देशों को नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए नए सहयोगियों की जरूरत है। नॉर्वे के व्यापार को भी नए अवसर चाहिए। ऐसे में भारत के साथ मजबूत संबंध दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल भाषण देने की नहीं, बल्कि भारत की बात सुनने की भी जरूरत है। अगर ऐसा हुआ, तो दोनों देशों के लिए कई नए अवसर खुल सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व चमत्कार अब विश्वभर में

बिल ड्रेक्सल (सीनियर फेलो, हडसन इंस्टीटयूट) – द वशिंगटन पोस्ट

सालों से, पश्चिमी उदारवादी और भारत का विपक्ष, दोनों ही खुद को एक सिद्धांत से सांत्वना देते रहे हैं: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक तानाशाह हैं; भारत की अभिभूत करने वाली विविधता, किसी 'मज़बूत नेता' के शासन के साथ मेल नहीं खाती; और इसलिए, उनकी श्अनुदारवादीश सोच का नतीजा स्वाभाविक रूप से उनके ही खिलाफ जाएगा।

इस सिद्धांत को शायद अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा, जब मोदी की भारतीय जनता पार्टी – जो इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है – ने उन राज्यों में से एक पर जीत दर्ज की, जहाँ उनकी पार्टी के लिए पहुँच बनाना सबसे ज़्यादा असंभव माना जाता था: एक बेहद स्वतंत्र और सांस्कृतिक रूप से अलग क्षेत्र, जिसकी आबादी कैलिफ़ोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क की कुल आबादी से भी अधिक है। विपक्ष के लिए यही बेहतर होगा कि वह अपनी इस हार से कुछ सीखने की कोशिश करे।

सोमवार की मतगणना ने सिर्फ़ एक राज्य में सत्ता बदलने से कहीं ज़्यादा काम किया। दशकों से, भारत की सबसे ताक़तवर क्षेत्रीय पार्टियाँ बीजेपी के राष्ट्रीय विस्तार के रास्ते में सबसे मज़बूत बाधा रही हैं – ये ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनकी जड़ें स्थानीय स्तर पर बहुत गहरी हैं, जो अपने राज्यों की भाषा और पहचान को अच्छे से समझती हैं और जिनमें बीजेपी की मुख्य रूप से उत्तर भारतीय, हिंदी–भाषी संस्कृति अक्सर सेंध लगाने में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व प्रभावशाली ममता बनर्जी करती हैं, इनमें से सबसे प्रमुख थी, जिसने इस विचार को और मज़बूती दी कि भारत की विविधता इतनी विशाल है कि कोई भी पार्टी इसे पूरी तरह से एक सूत्र में नहीं पिरो सकती – एक ऐसी पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की किसी विशिष्ट और आक्रामक दृष्टि को आगे बढ़ा रही हो। सोमवार को बनर्जी को पराजित करके, बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि अब वह उन क्षेत्रीय और सांस्कृतिक बाधाओं को भी तोड़ सकती है, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थीं।

इस जीत से पहले भी, बीजेपी के उभार से जुड़े आँकड़े पहले से ही चौंकाने वाले थे। बीजेपी के 140 मिलियन सदस्य हैं, जो पूरी दुनिया की किसी भी राजनीतिक पार्टी से अधिक हैं; यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी – जो इसकी एकमात्र समकक्ष है – की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। मानव इतिहास में किसी भी राजनेता की तुलना में मोदी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और यह अंतर सैकड़ों मिलियन का है। मॉर्निंग कंसल्ट के वैश्विक नेता अनुमोदन ट्रैकर में, मोदी ने कई सालों से दुनिया के हर दूसरे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को आसानी से पीछे छोड़ दिया है, भले ही उनका कार्यकाल कितना भी लंबा रहा हो। उन पैमानों के हिसाब से, जो लोकतंत्र में सत्ता का मतलब होते हैं, हिंदू दक्षिणपंथ पहले से ही समकालीन दुनिया का सबसे सफल राजनीतिक आंदोलन बन चुका है।

आलोचक इसके जवाब में कहते हैं – और उनके पास इसके कारण भी हैं – कि चुनावी सफलताएँ ही लोकतांत्रिक ताकत को मापने का एकमात्र तरीका नहीं हैं, और यह कि बीजेपी और व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन ने भारत की उदार संस्थाओं, प्रेस की आज़ादी और बहुलवादी सामाजिक ताने–बाने को कमज़ोर किया है, जिसके तहत उनके शासन में अल्पसंख्यकों को बढ़ती हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

वे आगे यह भी दावा करते हैं कि चुनाव उतने सरल नहीं हैं, जितने वे दिखते हैं और वे बीजेपी पर

चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में झुकाने का आरोप लगाते हैं – जैसे कि चुनाव आयोग में अपने लोगों को बिठाना और एक ऐसी चंदा योजना तैयार करना, जिसने पार्टी को अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में भारी वित्तीय लाभ पहुँचाया। हालांकि, यह योजना अब खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी एक विवाद खड़ा हो गया था, जब चुनाव आयोग ने मतदाता–सूची से लगभग 9 मिलियन नाम हटा दिए थे, जो मतदाताओं की कुल संख्या के लगभग 12 प्रतिशत थे। समर्थकों ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि ये नाम दोहराव, अयोग्य या मृत मतदाताओं के थे, जबकि आलोचकों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के एक हथियार के तौर पर इसकी निंदा की, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं।

लेकिन बीजेपी की सफलताओं के पीछे केवल चुनावी रणनीति ही नहीं है। सोमवार को पार्टी ने पश्चिम बंगाल की दो–तिहाई से ज़्यादा सीटें जीतीं, और 50 साल से भी कम समय में एक छोटी सी पार्टी से बढ़कर 21 राज्यों का नेतृत्व करने वाली पार्टी बन गई – जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने भारत को आज़ादी दिलाई थी, अब सिर्फ़ चार राज्यों तक सिमट गई है।

मुख्य प्रतिद्वंद्वी के साथ यह अंतर बहुत कुछ सिखाता है। कांग्रेस पार्टी को अपना प्रभुत्व विरासत में मिला था: इसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, भारत के अंग्रेज़ी बोलने वाले पढ़े–लिखे तबके का भरोसा जीता, देश के पहले 50 सालों में ज़्यादातर समय तक राज किया, देश के लिए संस्थाएँ बनाईं – ये संस्थाएँ समाज को प्रबंधित करने के बारे में उस समय के लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय विचारों से प्रेरित थीं। बीजेपी ने अपना प्रभुत्व कड़ी मेहनत से बनाया – ज़मीन से जुड़कर, दशकों तक ज़मीनी स्तर पर संगठन बनाकर, और बड़ी मेहनत से एक ऐसा गठबंधन तैयार करके, जिसमें अब अलग–अलग जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं के लोग शामिल हैं – ऐसे लोग, जिनके पास अन्यथा साथ में मतदान करने का कोई खास कारण नहीं होता है।

इसकी आधारशिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संघ परिवार या ष्संगठन परिवारष है। आरएसएस एक विवादित हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है, जो अब सौ साल पुराना हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य लाखों कार्यकर्ताओं और दर्जनों ऐसे संगठनों को तैयार करना है, जो हिंदू समाज को पुनर्जीवित करने के इसके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए समर्पित हों। बीजेपी के साथ मिलकर, आरएसएस उन अन्य संगठनों के नेटवर्क के ज़रिए अपना संदेश फैलाता है, जिनकी स्थापना उसने बीजेपी के साथ ही की थी: जैसे भारत का सबसे बड़ा मज़दूर संघ, निजी स्कूलों का सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा छात्र–संगठन और हिंदू धार्मिक नेतृत्व की सबसे प्रभावशाली परिषद–ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। भारतीय समाज में ज़मीनी स्तर पर, वैचारिक और सामाजिक संबंधों का यह अनूठा ताना–बाना–जिसमें कठोर सौदेबाज़ी और गठबंधन बनाने की चतुर कला भी शामिल है– बीजेपी के असाधारण उदय की नींव रहा है।

जब भारत दुनिया की महान शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है, ठीक उसी समय बीजेपी अपनी सत्ता को और मज़बूत कर रही है: आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा, सैन्य कर्मियों के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा बनने की राह पर, और एशिया में चीन का संतुलन करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र देश। पश्चिम बंगाल में सोमवार को मिली जीत यह दिखाती है कि बीजेपी का उभार अभी अपनी उच्चतम सीमा तक नहीं पहुँचा है।

बीजेपी के विरोधी उस न्याय की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसकी भविष्यवाणी वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। वह समय आ भी सकता है। लेकिन जो कोई भी मौजूदा हालात को देख रहा है, उसे इसके बजाय आने वाले दशकों के भारत – और एशिया में सत्ता के संतुलन – के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसे काफी हद तक शहिंदू दक्षिणपंथीश ही आकार देंगे।

•

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत सुक्खू सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और माफिया राज पर जनता का करारा प्रहार : जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री झूठे, उन पर मंत्री भी नहीं करते यकीन, ममता बनर्जी जैसी है सुक्खू की हालत

जयराम ठाकुर
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार, अराजकता और माफिया राज को जनता द्वारा पूरी तरह नकारने का स्पष्ट संदेश है। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय "दीप कमल" में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के झूठे वादों, जनविरोधी निर्णयों और कुशासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है, माफिया तत्वों को संरक्षण मिला है और भ्रष्टाचार ने शासन व्यवस्था को खोखला कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता अब कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री झूठे हैं और उन पर उनके मंत्री ही भरोसा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री चुनाव के परिणाम जानते थे इसी वजह से वह चुनाव से भागते रहे। अब वह परिणामों से विचलित हैं और ममता बनर्जी की तरह बातें कर रहे हैं। उन्हें आज का और आगे का भी जनादेश स्वीकार करना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह जीत केवल भाजपा की चुनावी सफलता नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के भाजपा के प्रति विश्वास और कांग्रेस सरकार के खिलाफ गहरे जनाक्रोश का प्रतीक है। जनता ने मुख्यमंत्री के झूठ, भ्रम और प्रचार की राजनीति को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी हार का अंदाज़ा पहले से था। यही कारण रहा कि कांग्रेस सरकार लगातार स्थानीय निकाय चुनावों से भागती रही और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही चुनाव करवाने पड़े। अब चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह मोहभंग कर चुकी है।

नेता प्रतिपक्ष ने इस ऐतिहासिक जीत में योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य चुनावों में भी जनता भाजपा को और अधिक समर्थन देकर कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश कोषाध्यक्ष कमल सूद, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा, प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंद, शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

डॉ. राजीव बिंदल
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी हि0प्र0

नगर परिषदों की 229 सीटों में भाजपा ने 120 सीटें जीतकर प्रदेश में बनाया नया राजनीतिक इतिहास

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश कार्यालय दीपकमल में संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास, भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और संगठन की ताकत की जीत है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश कांग्रेस सरकार की विफलताओं, झूठी गारंटियों और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ खुला जनमत संग्रह है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची तक जारी नहीं की, आज वही जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वयं मीडिया के सामने कहा था कि पार्टी अपनी ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करेगी और जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का जीत का दावा हास्यास्पद और जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ईमानदारी के साथ उन उम्मीदवारों को कांग्रेस समर्थित मान रही है जिनके खिलाफ भाजपा ने चुनाव लड़ा और उसी आधार पर चुनाव परिणामों का विश्लेषण जनता के सामने रखा जा रहा है। डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा को अगले आम चुनावों में भी जनता के बीच जाना है, इसलिए पार्टी तथ्यों और वास्तविक जनमत के आधार पर ही बात कर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों को लगातार टालने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अक्टूबर–नवंबर 2025 में हो जाने चाहिए थे और राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार था, लेकिन कांग्रेस सरकार चुनावों से भाग रही थी। अंततः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी।

डॉ. बिंदल ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद भाजपा ने पूरे प्रदेश में प्रभारी, सह–प्रभारी और चुनावी टीमों की नियुक्ति कर संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 25 नगर परिषदों की कुल 229 सीटों में भाजपा ने 120 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस को 89 सीटों पर जीत मिली और 20 सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजयी रहे। नगर पंचायतों में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक स्थानों पर स्पष्ट बढ़त हासिल की।

उन्होंने कहा कि यह जनादेश कांग्रेस सरकार के तीन वर्षों के कुशासन के खिलाफ जनता का स्पष्ट संदेश है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ता माफिया राज, गैंगवार, विकास कार्यों का ठप होना, संस्थानों को बंद करना, महंगाई, बिजली–पानी और परिवहन किरायों में वृद्धि तथा झूठी गारंटियों से जनता त्रस्त है। महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान किया है।

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस सरकार में बेचौनी है और मंत्री, विधायक तथा अधिकारी भाजपा समर्थित विजयी पार्षदों को डराने–धमकाने और प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनावों के नियमों में बदलाव कर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के राजनीतिक उपकरण न बनें और संविधान के अनुसार कार्य करें। अंत में डॉ. बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भी जनता कांग्रेस सरकार को जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प पर विश्वास जताएगी।

मोदी-शाह के चक्रव्यू से ममता बाहर नहीं निकल सकी

सिद्धार्थन, संगठन महामंत्री हि०प्र०

पश्चिमी बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जो अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ने अपनी पार्टी की जीत को हिंदुत्व की जीत बताया था। 15 साल के ममता के क्रूर शासन त्रस्त जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही चैन की सांस ली और अपने को सुरक्षित महसूस किया इन चुनावों में जहां मोदी–शाह जी की रणनीति ने काम किया वहीं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री पिछले 6 महिने से अपने–2 मोर्चों पर डटे रहे और कार्तकर्ताओं का मार्गदर्शन–मनोबल और भविष्य की योजना बनाते रहे। हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी का कहना था कि यह चुनाव कम और आमने–सामने का युद्ध अधिक था। टीएमसी के गुंडे सदा धमकियां देते रहते थे। लड़ाई झगड़े मार पीट करते रहते थे। उनके साथ हिमाचल से दर्जन भर से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ता बंगाल की विभिन्न सीटों पर रात दिन डटे रहे और विजय प्राप्त करके ही वापस लोंटे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली एकल जीत एक के बाद एक जीत की सहज प्रगति नहीं थी, बल्कि इसके लिए दशकों का संघर्ष करना पड़ा। वाजपेयी युग के दौरान ममता बनर्जी की नवगठित पार्टी तृणमूल कांग्रेस को केंद्र में एनडीए सहयोगी के रूप में शामिल करने से लेकर राज्य में सुश्री बनर्जी के चौथे कार्यकाल के प्रयास को रोकने के लिए एकमात्र मजबूत पार्टी बनने तक, यह एक लंबा और कठिन सफर रहा है।

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 18 सीटों की जीत के बाद 2021 के विधानसभा चुनावों में हार और 2024 में संसदीय सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। इसलिए, 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक योजना और संदेश का बिल्कुल सटीक होना आवश्यक था।

पुस्लिम प्रोफेसर कहते हैं :– अपनी बात जारी रखते हुए प्रोफ़ेसर महमूद कहते हैं, ''आरएसएस का काम लोगों के बीच धीरे.धीरे, नरमी से सांस्कृतिक असर डालना है और उनकी सोच बदलना है''

''आरएसएस हर जगह इसी तरह काम करता है. वह लोगों के लिए काम करता है, लेकिन उसके स्कूलों और उनके पाठ्यक्रम में एक ख़ास तरह की विचारधारा सिखाई जाती है. आखि़र में यही विचारधारा बीजेपी की राजनीतिक सोच और उसके राजनीतिक एजेंडे की मदद करती है.''

पश्चिमी बंगाल की जीत को देश विदेश के नामी समाचार पत्रों और मीडिया चैनलों में विशेष स्थान दिया तथा देश विदेश से प्रधानमंत्री व गृह मंत्री व पार्टी अध्यक्ष को बधाई संदेश मिलते रहे। वहां नई सरकार बनते ही वहां समान्य स्थिति बहाल करने और नागरिकों के भीतर विश्वास पैदा करने का क्रम चल रहा है। ममता सरकार ने केन्द्र की योजनाओं को लागू करने में आना कानी की और आम गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। उन योजनाओं को भी लागू करने की आवश्यकता है।

पिछले 15 सालों में ममता की अराजक सरकार का कहर झेल रहे कार्यकर्ताओं व पार्टी के लिये अपना बलिदान देने वाले कार्यकर्ताओं के पुर्नवास की भी योजना बनाना आवश्यक होगा।

पश्चिम बंगाल में पार्टियों की स्थिति इस प्रकार रही :–

''विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई– 2026 के रूझान एवं परिणाम

पश्चिम बंगाल (Total AC : 294)

बीजेपी – 207

एआईटीसी – 80

आईएनसी – 2

अपनी दोनों सीटें हारने के बाद बहुत खोने के बाद भी ममता ने इस्तीफा नहीं दिया–क्या कहा :–

ममता बनर्जी ने इस्तीफ़े के सवाल पर कहा, ''क्यों मैं क्यों जाऊंगी। हम तो हारे नहीं हैं कि जाएंगे। हार का सुबूत देते तो इस्तीफ़ा देते। ज़ोर–ज़बरदस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफ़ा देना होगा तो नहीं। अभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि हम चुनाव नहीं हारे हैं।''

उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुख्य विलेन है।

ममता बनर्जी ने कहा, ''पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रैटजी पर चर्चा की जाएगी. मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सड़कों पर लौटूंगी।''

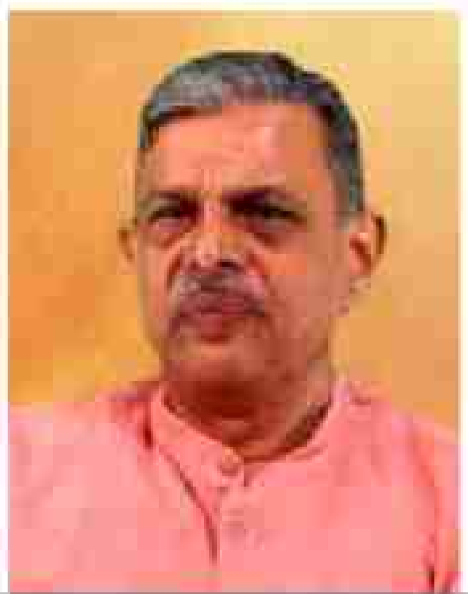

संघ का कार्य हिन्दू समाज को संगठित सशक्त एवं समर्थ बनाने के लिए चल रहा है

दत्तात्रेय होसबाले
सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

व्यक्तिगत चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही संघ कार्य का लक्ष्य। संघ का कार्य भारत को समरस, समर्थ एवं सशक्त बनाने की दिशा में चल रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कांगड़ा द्वारा होटल डी पोलो के सभागार में प्रमुख जन गोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी संघ कार्य की 100 वर्षों की यात्रा को पूर्ण किया है। इन सौ वर्षों में संघ ने सेवा एवं समर्पण भाव से देश सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। स्वतन्त्रता सेनानी एवं संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार जी ने भारत को स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए विजयदशमी 1925 के दिन संघ का कार्य प्रारम्भ किया। देश भक्ति से ओत–प्रोत एवं समाज का भला करने वाले व्यक्ति संघ की नित्य शाखा से निर्माण हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा की संघ भारत को अच्छा बनाने की दिशा में सामान्य व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र दोनों को ठीक करने की दृष्टि से कार्य कर रहा है। समाज की उन्नति के लिए समाज का संगठन करना, सामूहिक प्रयास करना, सबको साथ लेकर चलना यह भी अति आवश्यक है। देश के सर्वांगीण विकास में सभी का योगदान होना चाहिए। संघ सभी प्रकार के भेद–भाव को समाप्त कर समाज के लिए कार्य करता है। संघ केवल एक संगठन नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन है और संघ कार्यकर्ताओं के लिए एक जीवन शैली है। वर्तमान में अपना भारत देश दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। भारत दुनिया को जीवन जीने की शैली बता रहा है। अन्य देश भारत का अनुसरण भी कर रहे है।

कार्यक्रम में प्रमुख जनों द्वारा सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, सेवा कार्य एवं देश दुनिया की वर्तमान परिस्थिति, शिक्षा नीति, संस्कार पक्ष, संघ में महिलाओं की सहभागिता को लेकर प्रश्न भी पूछे गए जिनका सरकार्यवाह द्वारा ठीक प्रकार से उत्तर देकर समाधान किया। गोष्ठी में जिला कांगड़ा के भिन्न–भिन्न स्थानों से सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के आचार्य, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, प्रसिद्ध गायक, खिलाड़ी, समाचार पत्रों के मुख्य संपादक, जन प्रतिनिधि, अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं साधु–संतों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रान्त संघचालक डॉ. वीर सिंह रांगड़ा, सह प्रान्त संघचालक अशोक शर्मा विभाग संघचालक भूषण रैना, जिला संघचालक प्रदीप कुमार, क्षेत्र कार्यवाह रोशन यादव, डॉ. किस्मत कुमार, प्रान्त कार्यवाह डा. चंद्र प्रकाश, विपन कुमार, संजय कुमार, ओमप्रकाश, बलराम शर्मा, प्रताप समयाल, कुलपति सत प्रकाश बंसल, डॉ. क्षमा मैत्रेयी, सम्पादक हेमंत कुमार, नवनीत शर्मा, मदन लखेड़ा, रेखा कपूर, चंपा भारद्वाज, लोक गायिका पूनम भारद्वाज, प्रो. अनुपमा सिंह, अरुण चौतन्य सहित सैकड़ों प्रमुख बंधु भगिनि, समाज के प्रतिष्ठित जन एवं संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

समाज को सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् बनाना हमारा लक्ष्य

जब हम अपने आचरण और मूल्यों से दूर हो जाते हैं, तब संकट केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि परिवार, समाज और विश्व तक फैलते हैं। इसलिए धर्म को केवल पूजा–पद्धति या ग्रंथों तक सीमित समझना उचित नहीं है। धर्म जीवन जीने की एक सजीव प्रक्रिया है, जो कर्तव्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर चलती है। धर्म के चार आधार है सत्य, शुचिता, करुणा और तपस्या जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव और भगवान राम जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन से इन मूल्यों को साकार किया है। हम सभी के अपने–अपने कर्तव्य हैं, पुत्र धर्म, शिष्य धर्म, गुरु धर्म, राज धर्म, जब हम इनका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, तब ही सच्चे अर्थों में धर्म की स्थापना होती है। हमारा लक्ष्य है समाज को सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् बनाना और यही हमारे जीवन का पथ और प्रेरणा है।

हम महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगेः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 अप्रैल को भारत की माताओं, बहनों और बेटियों से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिलाओं की प्रगति रुकने पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सर्वोत्तम और ईमानदार प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पारित नहीं हो सका, जिससे महिलाओं के वैध सपने टूट गए। श्री मोदी ने कहा, "मैं देश की सभी माताओं और बहनों से इस दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम के लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं।"

राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने देश के कल्याण से अधिक अपने दलगत लाभों को प्राथमिकता दी।

देशभर में देखी गई गहरी निराशा पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक की विफलता महिलाओं के आत्मसम्मान पर एक सीधा आघात है, ऐसा अपमान जिसे महिला मतदाता कभी नहीं भूलेंगी। श्री मोदी ने कहा, "महिलाएं सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन वे अपने स्वाभिमान पर हुए अपमान को कभी नहीं भूलतीं।"

उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं ऐसे कुत्सित इरादों को भली-भांति समझती हैं और भविष्य में ऐसे आचरण के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाएंगी। श्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के परिवर्तनकारी विजन को विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधेयक लंबे समय से लंबित अधिकारों को प्रदान करने और आधी आबादी के लिए नए अवसर सृजित करने का एक व्यापक प्रयास था। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना और सभी राज्यों की राजनीतिक शक्ति को समान रूप से सुदृढ़ करना था, चाहे उनका आकार या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। श्री मोदी ने कहा, "यह संशोधन भारत की विकास यात्रा में महिलाओं को समान सहभागी बनाने का एक ईमानदार प्रयास था।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत के नागरिक इस प्रकार की राजनीति के नकारात्मक तरीके को पूरी तरह समझ चुके

हैं और इसके पीछे छिपे इरादों से भी भली-भांति अवगत हैं। श्री मोदी ने कहा, "देश अब महिलाओं के अधिकारों को छीनने के लिए अपनाए जाने वाले इस नकारात्मक राजनीतिक तरीकों को पूरी तरह समझ चुका है।"

आशंकित हैं परिवारवादी पार्टियां

श्री मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां इस बात से आशंकित हैं कि उनके परिवारों के बाहर की सशक्त महिलाएं उनके स्थानीय नेतृत्व को चुनौती दे सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंचायतों में कार्यरत हजारों सक्षम महिलाएं इन परिवारवादी राजनेताओं की गहरी जमी हुई असुरक्षा को सीधे चुनौती दे रही हैं।

झूठे कथनों को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी राज्य की प्रतिनिधित्व संख्या कम नहीं होगी, बल्कि सभी राज्यों की सीटों में समान और न्यायसंगत अनुपात में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय विकास के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस संशोधन से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की संसदीय सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती थी।

श्री मोदी ने पहले विरोध किए गए कई परिवर्तनकारी कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि जन-धन-आधार-मोबाइल त्रयी, डिजिटल भुगतान, जीएसटी और तीन तलाक के खिलाफ कानून का भी विरोध किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सीएए कानून को लेकर भी भ्रम फैलाया गया और माओवादी हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में लगातार बाधाएं उत्पन्न की गईं।

जन-धन-आधार-मोबाइल त्रयी, डिजिटल भुगतान, जीएसटी और तीन तलाक के खिलाफ कानून का भी विरोध किया गया था। पहले सीएए कानून को लेकर भी भ्रम फैलाया गया और माओवादी हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में लगातार बाधाएं उत्पन्न की गईं

आवश्यक निर्णयों को लंबे समय तक टालने की रही प्रवृत्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के ऐतिहासिक विकास में हुई देरी का उल्लेख करते हुए कहा कि आवश्यक निर्णयों को लंबे समय तक टालने की प्रवृत्ति के कारण ही आजादी के बाद कई अन्य दूसरे देश भारत से आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि लगभग 40 वर्षों तक सीमा विवादों के समाधान, ओबीसी आरक्षण और सैनिकों के लिए वन-रैंक-वन-पेंशन जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं पर ठोस निर्णय लेने में देरी हुई।

श्री मोदी ने कहा कि ऐसे निर्णयहीनता और छल-प्रपंच के कारण ही भारत की कई पीढ़ियों को गहरा नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा राजनीतिक संघर्ष सिर्फ एक विधेयक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक लड़ाई है जो सुधार-विरोधी मानसिकता के खिलाफ है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि देश की सभी बहनें और बेटियां इस नकारात्मक मानसिकता का करारा जवाब देंगी।"

इस दावे को खारिज करते हुए कि विधेयक का पास न होना सरकार की छवि को प्रभावित करता है, प्रधानमंत्री ने दोहराया कि यदि विपक्ष ने इस कानून का समर्थन किया होता, तो वे विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें पूरा श्रेय देने के लिए तैयार थे। श्री मोदी ने कहा, "यह मुद्दा कभी राजनीतिक श्रेय लेने का नहीं था; यह अधिकारों को सुरक्षित करने करने के बारे में था।"

महिला सशक्तीकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

महिला सशक्तीकरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की करोड़ों महिलाओं द्वारा महसूस किए गए दुःख के साथ एकजुटता व्यक्त की और उन्होंने आश्वस्त किया कि संसद में संख्या बल की कमी के बावजूद उनका संकल्प, हमारा आत्मबल दृढ़ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेगी और अंततः इसमें देश की 100 प्रतिशत महिलाओं के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करेगी। श्री मोदी ने कहा, "आधी आबादी के सपनों और देश के भविष्य के लिए हमें इस संकल्प को पूरा करना ही होगा।" ■

कार्यकर्ताओं के तप से भाजपा आज देश की सबसे भरोसेमंद पार्टी बनी है : नरेन्द्र मोदी

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल, 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का माध्यम है, जिसने 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत को भारत की राजनीति का केंद्र बना दिया। उन्होंने कहा करोड़ों मेहनती और समर्पित कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और तितिक्षा से भाजपा आज देश की सबसे भरोसेमंद पार्टी बनी है। भाजपा आने वाले समय में घुसपैठ, भ्रष्टाचार, परिवारवाद तथा गुलामी की मानसिकता जैसी चुनौतियों से देश को मुक्त कर विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी पूरा करेगी।

भाजपा कार्यकर्ताओं की अटूट आस्था और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी भविष्य पर से भरोसा नहीं खोया। आपातकाल, कांग्रेस के षड्यंत्र, राजनीतिक बहिष्कार की कोशिशें और कई राज्यों में हिंसा के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता कभी डिगे नहीं। बंगाल और केरल जैसे राज्यों में राजनीतिक हिंसा के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रसेवा का अपना संकल्प बनाए रखा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली प्रेरणा ने भाजपा को शुचिता और साफ नीयत के साथ राजनीति करने की दिशा दी।

भाजपा की सेवाभाव और जनकल्याण की राजनीति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधन सीमित होने के बावजूद पार्टी ने हमेशा जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। चाहे आपदा का समय हो या समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन, भाजपा कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच उपस्थित रहे। इसी सेवाभाव ने लोगों का भाजपा पर विश्वास लगातार मजबूत किया। भाजपा ने अपने आचरण से देश में 'राष्ट्र प्रथम' की राजनीति को स्थापित किया और राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि बनाया।

गठबंधन राजनीति में भाजपा की भूमिका पर श्री मोदी ने कहा कि देश में अनेक गठबंधन बने, लेकिन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर गठबंधन बनाने का कार्य भाजपा ने ही किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए आज 25 वर्षों से अधिक पुराना हो चुका है और लगातार उसका विस्तार यह दर्शाता है कि भाजपा क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए सर्वसमावेशी राजनीति करती है।

मुख्य बिंदु

हमने नारी शक्ति वंदन एक्ट लाकर अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली है और इसे 2029 के चुनावों में लागू करने का लक्ष्य रखा है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों से प्रेरित होकर भाजपा ने 'स्वच्छ और मूल्य-आधारित शासन' की प्रतिबद्धता के साथ राजनीति में प्रवेश किया

महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था और संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प लिया था। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने महिला आरक्षण का वादा पूरा किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा आज गुड गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी का प्रतीक बन चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा सरकार ने सैचुरेशन मॉडल अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए।

श्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में भाजपा सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों को समाप्त करना, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, नए संसद भवन का निर्माण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण, तीन तलाक पर रोक, सीएए कानून और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे अनेक कार्य भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे विषयों पर भी देश में गंभीर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ही वर्षों में भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें नए लक्ष्यों का मंथन भी करना है और बदलती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में खुद को ढालना भी है। ■

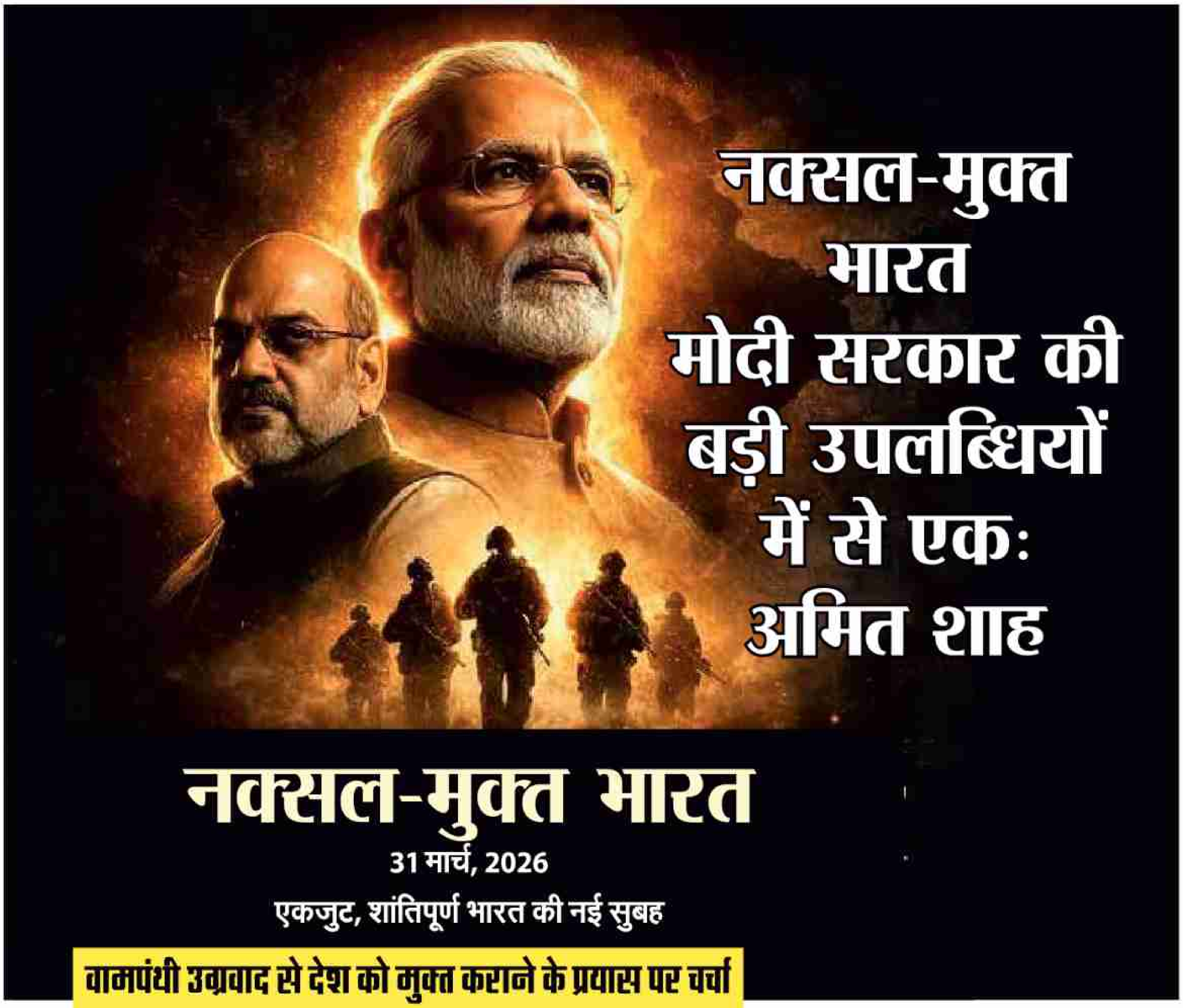

वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 मार्च, 2026 को लोकसभा में नियम 193 के तहत देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवादियों और उनके समर्थकों ने भोले-भाले आदिवासियों के सामने एक झूठा नैरेटिव प्रस्तुत किया था कि वे उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर से अब नक्सलवाद लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है और वहां के प्रत्येक गांव में स्कूलों के निर्माण तथा राशन की दुकानों के संचालन का अभियान शुरू हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग नक्सलवाद की वकालत करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1970 से लेकर अब तक ये कार्य क्यों नहीं हुए। श्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के समर्थकों ने 1970 से मार्च, 2026 तक लगातार नक्सलवाद का समर्थन किया है। यह नरसंहार का समर्थन है और यदि 20,000 लोगों की हत्या के पीछे किसी एक विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया जाए, तो वह मुख्य विपक्षी दल की वामपंथी विचारधारा है। नक्सलियों के साथ रहते-रहते यह पार्टी और इसके नेता स्वयं ही नक्सली बन गए हैं। श्री शाह ने कहा कि इस देश की जनता को चुनावों में इसका उत्तर देना होगा, क्योंकि यह मामला यहीं नहीं रुकेगा— यह जनता की अदालत में जाएगा। लोकसभा में श्री अमित शाह द्वारा दिए गए उत्तर का पाठ निम्नलिखित है:

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। संसद के विशेष सत्र के दौरान एनडीए सरकार ने लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करना था। आज लोकसभा में इस विधेयक के खिलाफ मतदान करके कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडी' गठबंधन ने अपने महिला-विरोधी चरित्र को उजागर कर दिया है। यह कानून केवल एक विधेयक मात्र नहीं था; यह 'नारी शक्ति' को सशक्त बनाने और उन्हें उचित गरिमा प्रदान करने का एक अवसर था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र ने सभी राजनीतिक दलों से दलीय राजनीति से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की थी; हालांकि, विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की खातिर महिलाओं के सशक्तीकरण और गरिमा के उद्देश्य की बलि चढ़ा दी। पूरा देश हमेशा याद रखेगा कि विपक्ष ने राष्ट्रीय और सामाजिक भलाई के ऊपर अपने स्वयं के राजनीतिक स्वार्थों को प्राथमिकता दी। विपक्ष के इस महिला-विरोधी निर्णय ने उनके कथनी और करनी के बीच के घोर विरोधाभास को बेनकाब कर दिया है। देश की जनता अब उनसे सीधे तौर पर जवाब मांगेगी। लोकसभा में विधेयक के पारित न हो पाने के बावजूद हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। एनडीए सरकार महिलाओं की गरिमा और सशक्तीकरण के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। (18 अप्रैल, 2026)

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

यदि यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित हो जाता है, तो यह हमारे देश की महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा और हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। आइए, आज हम सब मिलकर इतिहास रचें। (17 अप्रैल, 2026)

शोभा करंदलाजे, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

आज नई दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडी' गठबंधन के उस फ़ैसले की कड़ी निंदा की गई, जो देश की महिलाओं की प्रगति और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बाधा डालता है। देश की महिला समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के दूरदर्शी उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रस्तावित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' विधेयक को कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडी' गठबंधन ने विफल करके देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा किए गए इस विश्वासघात को देश की पूरी आबादी, विशेष रूप से महिलाएं, कभी माफ़ नहीं करेंगी।

(18 अप्रैल, 2026)

जगत प्रकाश नड्डा

केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

आज लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 का पारित न हो पाना कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की महिला-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। यह केवल एक विधेयक का गिरना नहीं है, बल्कि उन लाखों बहनों के भरोसे का टूटना है, जिसे उन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए संजोकर रखा था। एक ओर जहां हम महिलाओं को 'शक्ति' मानकर उन्हें सशक्त बनाने का सपना देखते हैं, वहीं विपक्ष की संकीर्ण सोच ने उनकी प्रगति के मार्ग में एक दीवार खड़ी कर दी है। यह उनके सपनों और उनकी क्षमताओं का अपमान है।

'नारी शक्ति' का यह अपमान विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा! यह आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनावों से लेकर हर छोटे-बड़े चुनाव तक देश की बहनें अपने सपनों को कुचलने वालों को एक कड़ा सबक सिखाएंगी। याद रखना, शक्ति का यह रोष ही तुम्हारे राजनीतिक अंत की शुरुआत है।

(18 अप्रैल, 2026)

अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

इंडी गठबंधन = महिला-विरोधी गठबंधन! कल का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो सकता था; लेकिन इसके बजाय, राहुल गांधी और 'महिला-विरोधी गठबंधन'— जिसमें कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल हैं— ने देश की आधी आबादी के अधिकारों पर करारा प्रहार किया है। देश की महिलाएं इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगी। इस विधेयक को विफल करके, पूरे इंडी गठबंधन— जिसमें कांग्रेस भी शामिल है— ने अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है।

(18 अप्रैल, 2026)

वानथी श्रीनिवासन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और डीएमके सरकार तमिलनाडु की महिलाओं और उसके भविष्य को संवारने में नाकाम रहे हैं। परिसीमन के ढांचे का आंख मूंदकर विरोध करके राज्य ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। इसके बजाय, तमिलनाडु पर अब 2026 के बाद और भी सीटें गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। महिला आरक्षण को रोकने से लेकर संसद में तमिलनाडु की आवाज को कमज़ोर करने तक, यह शासन नहीं, बल्कि है। डीएमके आखिर किस बात का जश्न मना रही है— गंवाए हुए मौकों का या दांव पर लगे भविष्य का?

(18 अप्रैल, 2026)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का लोक सभा में परिसीमन विधेयक 2026, संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक, 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा का उत्तर

विपक्षी गठबंधन ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 अप्रैल को लोक सभा में परिसीमन विधेयक 2026, संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा का उत्तर दिया। श्री शाह ने कहा कि इस चर्चा में 130 सदस्यों ने अपनी बात रखी है, जिनमें 56 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विरोध अमल के तरीकों का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण का विरोध है। श्री शाह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि संविधान सभा द्वारा हमारे लोकतंत्र की नींव में रखे गए एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत को लागू किया जाए

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या बढ़ती है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतुलित, समावेशी और व्यावहारिक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करने की ज़िम्मेदारी संविधान ने सरकार को दी है और अभी यह ज़िम्मेदारी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। श्री शाह ने कहा कि संघीय संतुलन बनाए रखना, लोक सभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व लाना और राज्यों की शक्तियों के बीच संतुलन बनाना भी परिसीमन के उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं, शहरीकरण और सड़क, रेल आदि से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए ज़िलों का संज्ञान भी परिसीमन मे लेना होता है। श्री शाह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में इन सभी सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उनके निर्वहन के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संविधान संशोधन लाई है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे के निर्माण करने की ज़िम्मेदारी के निर्वहन से ही ये विधेयक आए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नारीशक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1971 में विपक्षी पार्टी की सरकार ने इसे फ्रीज़ किया था और इसी कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा है। श्री शाह ने कहा कि 1971 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज़ रही है और आज 127 सीटें ऐसी हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक वोटर्स हैं। इन सीटों पर एक मत, एक वोटर और एक मूल्य के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन होता है।

सर्वप्रथम 1972 में सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर इसे फ्रीज किया गया

श्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545

संबोधन की मुख्य बातें

मुख्य विपक्षी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया — शाहबानो मामला हो, ट्रिपल तलाक का अंत हो, या लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण

1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौरान सत्ता बचाने के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी थी और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी ने ही परिसीमन को रोकने का काम किया

मोदी सरकार तीन दशकों से रिजेक्ट होते आ रहे महिला आरक्षण के लिए letter and spirit में बिल लेकर आई, मगर विपक्ष ने इसे पारित नहीं होने दिया

विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा

महिलाओं को सबल बनाने और विधायी संस्थाओं में उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए हमें चाहे किसी भी विरोध का सामना क्यों न करना पड़े, हम संघर्ष करते रहेंगे

किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। उस वक्त भी मुख्य विपक्षी पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी ही देश को परिसीमन से वंचित रख रही है। उन्होंने कहा कि 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। 1976 से 2026 तक के 50 वर्षों तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। श्री शाह ने कहा कि 2026 में यह सीमा समाप्त हो गई है और अब परिसीमन करने पर यह प्रक्रिया 2029 से पहले पूरी नहीं हो सकता क्योंकि परिसीमन आयोग को हर मतक्षेत्र में जाकर पब्लिक हियरिंग देनी होती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1976 में देश की आबादी 54.79 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि जब सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के कामकाज के दिनों की संख्या भी बढ़ाए। श्री शाह ने कहा कि हम हर राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं जिससे किसी भी राज्य का प्रोरेटा नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना समय पर क्यों नहीं हुई। श्री शाह ने कहा कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड का संकट आया और उसके कारण जनगणना संभव नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को इससे उबरने में काफी समय लगा। श्री शाह ने कहा कि जब 2024 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित मांग उठाई कि जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब जो जनगणना हो रही है उसमें जाति की गणना भी होगी। श्री शाह ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी के समय में पहले जो भी जनगणना हुई, उस समय जाति जनगणना नहीं होती थी और न ही कभी धर्म पूछा जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2026 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब से यह बिल आया है तब से विपक्ष ने भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली भ्रांति फैलाई गई कि जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार यह संविधान संशोधन लेकर आई है। श्री शाह ने कहा कि सरकार तीन माह पहले ही जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुकी है, इसीलिए जाति जनगणना को टालने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि एक और भ्रांति फैलाई गई कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय होगा। श्री शाह ने कहा कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष को उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव के साथ देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करने चाहिए बल्कि इससे ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली है, वे लोग उत्तर-दक्षिण का भेद करना चाहते हैं जो हम कभी नहीं होने देंगे। श्री शाह ने कहा कि जो भी सदस्य संसद में शपथ लेता है, वह भारत को अक्षुण्ण रखने और पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने राज्य, अपने धर्म और अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। गृह मंत्री ने कहा कि देश का विभाजन कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता।

1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। उस वक्त भी मुख्य विपक्षी पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी ही देश को परिसीमन से वंचित रख रही है। 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। 1976 से 2026 तक के 50 वर्षों तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला

कांग्रेस के नेतृत्व वाले महिला विरोधी गठबंधन ने देश की आधी आबादी के साथ घोर विश्वासघात किया है : नितिन नवीन

देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली इस देश की महिलाएं अब कांग्रेस और उसके महिला विरोधी गठबंधन के खिलाफ दृढ़ता और एकजुटता के साथ खड़ी होंगी और पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि यह संकल्प एक सशक्त सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने 17 अप्रैल, 2026 को संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों खासकर समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके द्वारा लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान और नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के मार्ग में बार-बार रोड़े अटकाने को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष के इस कृत्य ने उनके स्पष्ट महिला विरोधी सोच एवं उनकी मानसिकता को बेनकाब कर दिया है।

कांग्रेस गठबंधन का महिला विरोधी चरित्र उजागर

श्री नवीन ने कहा कि यह दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता था, परंतु कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले उनके महिला विरोधी गठबंधन ने देश की आधी आबादी के साथ घोर विश्वासघात किया है। आज लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन का असली महिला-विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा कि यह अवसर महिलाओं की उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता था, किंतु कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं को उनके न्यायोचित अधिकारों और हिस्सेदारी से वंचित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से कांग्रेस गठबंधन का महिला विरोधी चरित्र पूरी तरह और स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने और विशेष रूप से स्वयं प्रधानमंत्रीजी ने, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी अपने लिए कोई श्रेय नहीं चाहती। यह लड़ाई पहचान के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है। श्रेय लेने की बात तो दूर कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में अपने ही हितों के विरुद्ध कार्य किया और इस प्रक्रिया में अपनी स्वयं की साख को भी ठेस पहुंचाई।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके 'महिला विरोधी गठबंधन' ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित न होने देकर देश की नारी शक्ति के साथ घोर विश्वासघात किया है। जिस कांग्रेस ने दशकों तक महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा, आज उसने उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी की सरेआम हकमारी की है, जो करोड़ों माताओं-बहनों के सपनों पर एक कायरतापूर्ण प्रहार है।

भाजपा इस मुद्दे को सड़कों पर लेकर जाएगी

श्री नवीन ने आश्वस्त किया कि जिस प्रकार माताओं और बहनों को उनका न्यायोचित हक देने से वंचित किया गया है, उसे देखते हुए भाजपा इस मुद्दे को निर्णायक रूप से सड़कों पर लेकर जाएगी। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली इस देश की महिलाएं अब कांग्रेस और उसके महिला विरोधी गठबंधन के खिलाफ दृढ़ता और एकजुटता के साथ खड़ी होंगी और पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि यह संकल्प एक सशक्त सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए।

उन्होंने कहा कि भले ही यह विधेयक संसद में संख्या की दृष्टि से गिर गया हो, परंतु विपक्ष का महिला विरोधी गठबंधन देश भर की नारी शक्ति के दिलों में पहले ही स्थायी रूप से गिर चुका है। उन्होंने सदन के भीतर राहुल गांधी और उनकी टीम द्वारा प्रयुक्त भाषा पर गहरा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आचरण में झलकती अराजक मानसिकता उन्हें अत्यंत व्यथित करती है। उन शब्दों को दोहराने से परहेज करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि ऐसी मानसिकता को आने वाले समय में इस देश की महिलाओं की ओर से करारा जवाब मिलेगा।

श्री नवीन ने कहा कि खोखले वादे और नारी शक्ति का बार-बार अपमान करना ही कांग्रेस की असल राजनीति रही है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश महिलाओं को 'शक्ति' मानकर उन्हें नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है, वहीं विपक्ष की यह नकारात्मक सोच उनके विकास विरोधी चरित्र को दर्शाती है। नारी शक्ति का यह आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है और आगामी चुनावों में देश की माताएं-बहनें अपने अधिकारों को रौंदने वालों को कड़ा सबक सिखाते हुए इस विश्वासघात का पूरा हिसाब चुकता करेंगी। ■

किसानों, युवाओं, भारत-न्यूजीलैंड एफटीएः नौकरियों और विकास के लिए महिलाओं के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक समझौता

पीयूष गोयल

लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं

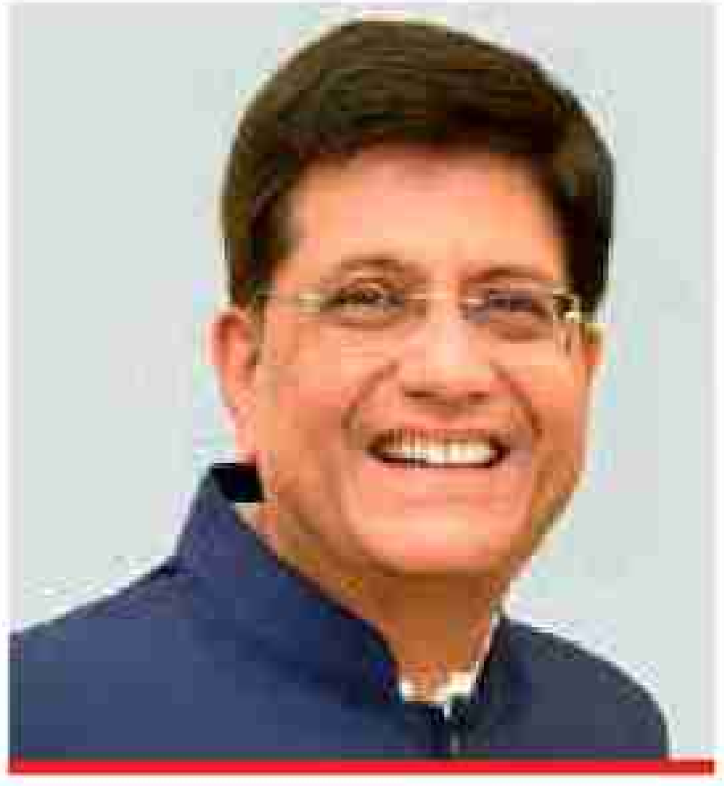

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिस पर सोमवार को हस्ताक्षर किये जायेंगे, विकसित दुनिया के साथ भारत की सहभागिता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को किसानों, महिलाओं, युवाओं और रोजगार सृजक उद्योगों के लिए ठोस लाभ में बदलने से जुड़े प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण में हुई निर्णायक प्रगति को प्रतिबिंबित करता है।

यह एफटीए प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ शामिल हैं, के साथ हुए कई ऐतिहासिक व्यापार समझौतों के बाद हो रहा है। ये समझौते वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं और निर्यातकों को दुनिया की कुछ सबसे लाभकारी अर्थव्यवस्थाओं में, यहां तक कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता और उथल-पुथल के बीच भी, प्रतिस्पर्धा आधारित बढ़त प्रदान करते हैं।

निर्यात और रोजगार को मजबूत बढ़ावा

दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी इस समझौते के केंद्र में न्यूज़ीलैंड की यह प्रतिबद्धता है कि वह तुरंत ही सभी भारतीय उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर देगा, जिससे उस बाजार में एक महत्वपूर्ण बाधा दूर होगी, जहां हमारे प्रमुख निर्यात पर वर्तमान में 10% शुल्क लगाया जाता है।

यह वस्त्र, कालीन, धागे, कपड़े, फुटवियर, बैग, बेल्ट, वाहन घटक, मशीनरी, उपकरण, रत्न और आभूषण तथा हस्तशिल्प जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाले ये उद्योग भारत के एमएसएमई इकोसिस्टम की रीढ़ हैं और इन्हें मूल्य प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच से लाभ मिलेगा। इससे निर्यात बढ़ेगा और निर्माण केन्द्रों, कारीगर समुदायों और लघु उद्यमों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

यह समझौता उस व्यापक दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद से भारत की व्यापार नीति का मार्गदर्शन कर रहा है। यह समावेश, सशक्तीकरण और साझा समृद्धि में निहित है। व्यापार को राष्ट्रीय परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाता है।

नारी शक्ति

इस समझौते की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए है। वार्ता टीम की लगभग सभी सदस्य महिलायें थीं। इनमें मुख्य वार्ताकार, उप मुख्य वार्ताकार, क्षेत्र प्रमुख और न्यूज़ीलैंड में भारत की राजदूत शामिल हैं।

यह उपलब्धि मोदी सरकार में महिलाओं के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। यह शासन, नेतृत्व और विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है और राष्ट्रीय विकास के संचालक के रूप में नारी शक्ति के विचार को सुदृढ़ करती है।

किसान पहले

एफटीए की संरचना कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गयी है। न्यूज़ीलैंड कीवी, सेब और शहद के लिए कृषि उत्पादकता कार्ययोजनाओं का समर्थन करेगा। इन पहलों में बेहतर बीज सामग्री, अनुसंधान सहयोग, किसानों के लिए क्षमता निर्माण, बागवानी प्रबंधन प्रथाएं, कटाई के बाद सुधार, खाद्य सुरक्षा प्रणाली और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है। सेब उत्पादकों और सतत मधुमक्खी पालन तौर-तरीकों के लिए परियोजनाएं उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाएंगी, जिससे कृषि समृद्धि में वृद्धि होगी।

दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी इस समझौते के केंद्र में न्यूजीलैंड की यह प्रतिबद्धता है कि वह तुरंत ही सभी भारतीय उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर देगा, जिससे उस बाजार में एक महत्वपूर्ण बाधा दूर होगी, जहां हमारे प्रमुख निर्यात पर वर्तमान में 10% शुल्क लगाया जाता है

लेख

रेल पटरियों का आधुनिकीकरण

अश्विनी वैष्णव

लेखक केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं

भारत में हर दिन 25,000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। वे प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को ले जाती हैं और कोयला, लौह अयस्क, अनाज, स्टील, सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं की बड़ी मात्रा को 1,37,000 किलोमीटर से अधिक लंबे रेल नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं।

पूरी व्यवस्था जिस आधार पर काम करती है, वह रेल पटरी है। जब पटरी अच्छी स्थिति में होती है, तब ट्रेनें सुरक्षित रूप से अधिक गति से चलती हैं। लेकिन जब पटरी खराब होती है, तो इसके परिणाम गति पर रोक, देरी और सुरक्षा संबंधी जोखिम के रूप में सामने आते हैं। रेल की पटरी में दरार, कोई ढीला पुर्जा या गिट्टी की परत में रुकावट, इनमें से कोई भी चीज ट्रेन की चाल को प्रभावित कर सकती है।

रेल पटरियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक दशक से अधिक समय पहले व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्य में आधुनिक मशीनों से पटरियों का नवीनीकरण, उन्नत तरीकों से जांच और निरीक्षण, मशीनीकृत रखरखाव, सुरक्षा बाड़बंदी आदि शामिल थे। इन सभी प्रयासों ने मिलकर रेल नेटवर्क की स्थिति को स्पष्ट रूप से बदल दिया है।

2014 से अब तक लगभग 55,000 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे सुरक्षा और यात्रा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा बार-बार मरम्मत की आवश्यकता कम हुई है। लगभग 44,000 ट्रैक किलोमीटर में 260 मीटर लंबे रेल पैनल बिछाए गए हैं। लंबे पैनलों का अर्थ है कम जोड़, जिससे ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम और सुरक्षित होती है। अब 80,000 ट्रैक किलोमीटर से अधिक हिस्से में मजबूत 60 किलोग्राम वाली रेल पटरियों का उपयोग हो रहा है, जो अधिक भार और तेज गति का समर्थन करती हैं।

मजबूत रेल पटरी बिछाना जरूरी है, लेकिन समय रहते खराबी पकड़ना भी उतना ही जरूरी है। छिपी हुई दरारों को खोजने के लिए अल्ट्रासोनिक जांच की गई है। इसके तहत करीब 36.2 लाख ट्रैक किलोमीटर और 2.25 करोड़ वेल्ड की जांच हुई। इससे रेल और वेल्ड टूटने की घटनाएं करीब 90 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। यानी अब खराबी होने के बाद उसे ठीक करने के बजाय पहले ही पकड़कर रोक लिया जाता है।

अब रेलवे में दूसरी आधुनिक जांच तकनीकें भी इस्तेमाल हो रही हैं। नई वेल्ड की जांच के लिए चुंबकीय जांच, फ्लैश-बट वेल्ड की जांच के लिए नई मशीनें और जीपीएस से जुड़ी ऐसी व्यवस्था लगाई गई है, जो ट्रेन की यात्रा की गुणवत्ता मापती है और पटरी के खराब हिस्से की सही जगह बता देती है।

भारतीय रेलवे की ट्रैक मशीनों की संख्या 2014 में 748 थी, जो 2026 में बढ़कर 1,785 हो गई है। ये मशीनें पटरी को ठीक करने, गिट्टी साफ करने और रेल को घिसकर बराबर करने का काम हाथ से होने वाले काम की तुलना में ज्यादा तेज, बेहतर और एक समान तरीके से करती हैं।

पटरी के नीचे बिछी गिट्टी की परत को साफ करने में मशीनों ने बड़ा फर्क पैदा किया है। यही गिट्टी पानी निकालने, कंपन कम करने और पटरी को मजबूत बनाए रखने का काम करती है। लेकिन समय के साथ ट्रेनों के लगातार वजन और कंपन से ये पत्थर टूटकर पाउडर जैसे हो जाते हैं। इससे गिट्टी की परत जाम हो जाती है और वह ठीक से काम नहीं कर पाती।

इसलिए गिट्टी की सफाई की जाती है, ताकि पटरी फिर से सही हालत में आ जाए। यह काम एक लाख किलोमीटर से ज्यादा रेल पटरियों पर किया जा चुका है और ज्यादातर काम मशीनों से हुआ है। इसी तरह पटरी की ऊपरी सतह की खराबी दूर करने के लिए भी एक लाख किलोमीटर से ज्यादा रेल की ग्राइंडिंग की गई है। इससे ट्रेन का सफर ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित हुआ है।

हर साल ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ट्रेनों के बीच रखरखाव के लिए मिलने वाला समय कम होता जा रहा है। ऐसे में मशीनों की मदद से कम समय में ज्यादा काम हो जाता है और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित नहीं होतीं। लेकिन सुरक्षा सिर्फ पटरी पर नहीं, बल्कि वहां भी जरूरी है जहां ट्रेनें लाइन बदलती हैं। इसलिए भारतीय रेलवे ने पटरी बदलने के साथ कई दूसरे सुधार भी किए हैं। करीब 17,500 किलोमीटर तक सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई गई है, खासकर उन जगहों पर जहां ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। इससे लोगों और जानवरों के पटरी पर आने की घटनाएं कम होती हैं।

जहां ट्रेनें एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाती हैं, वहां 36,000 नए और मजबूत स्विच लगाए गए हैं और 7,500 खास तरह के क्रॉसिंग लगाए गए हैं। ये ज्यादा समय तक चलते हैं और ट्रेन को बिना झटके के गुजरने देते हैं। 2019 से चौड़े और भारी स्लीपर लगाए जा रहे हैं, जिससे पटरी ज्यादा मजबूत रहती है, खासकर गर्मियों में। पुलों पर भी मजबूत स्लीपर लगाए गए हैं और यार्ड के अंदर लंबी वेल्ड वाली पटरियां बिछाई गई हैं।

दीपकमल संदेश
मासिक पत्रिका

भारत की औषधि रणनीतिः पैमाने से नवाचार की ओर

जगत प्रकाश नड्डा

लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं

वैश्विक स्तर पर कुल औषधि राजस्व में बायोलॉजिक, बायोसिमिलर और विशेष दवाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। लंबे समय से जेनरिक दवाओं में अग्रणी देश होने के कारण 'विश्व की फ़ार्मेसी' के रूप में प्रसिद्ध भारत का औषधि उद्योग अब पैमाने से नवाचार की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार भविष्य के अनुरूप एक नीतिगत रूपरेखा को गति दे रही है, ताकि देश जेनरिक दवाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए इन उभरते क्षेत्रों में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त कर सके।

केंद्रीय बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ के मिशन बायोफार्मा निर्माण शक्ति की घोषणा इस दिशा में एक निर्णायक कदम को रेखांकित करती है। यह अगले 8 से 10 वर्षों में भारत को बायोफार्मा नवाचार और उच्च मूल्य वाली चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक केन्द्र बनाने के देश के संकल्प का संकेत देती है। यह विज़न गहरी वैज्ञानिक क्षमताओं के निर्माण, नवाचार-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और भारत को अगली पीढ़ी की दवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने में सक्षम बनाने पर आधारित होगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और उन्नत चिकित्सीय क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को गति देना है। यह कार्यक्रम औषधि विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मौजूदा पहलों का पूरक है, जैसे फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (पीआरआईपी), अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, बायोनेस्ट आदि, जिनका उद्देश्य जैव-औषधि समेत जीवन विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। ये पहलें भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने, उद्योग-अकादमी सहयोग को बढ़ावा देने तथा जेनेरिक दवाओं से नवाचार संचालित दवा अनुसंधान और विकास की ओर बदलाव को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ किण्वन-आधारित निर्माण क्षमताओं का विकास करना है। एंटिबायोटिक, वैक्सीन, एंज़ाइम और बायोलॉजिक्स के निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद यह क्षेत्र लंबे समय से आयात पर निर्भर रहा है। अवसंरचना में निवेश करके, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाकर तथा लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके, भारत इस रणनीतिक क्षेत्र में घरेलू क्षमता का निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

भारत के नैदानिक अनुसंधान इकोसिस्टम का विस्तार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रयोग केंद्र स्थापित किये जायेंगे, जो वैश्विक दवा विकास गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को बेहतर बनायेंगे। अपनी लागत लाभ और कुशल शोधकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ भारत कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक प्रयोग के लिए असाधारण अवसर प्रदान करता है। साथ ही, नियामक व्यवस्था को मजबूत करने और संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने से भारत की मौजूदा व्यवस्था वैश्विक मानकों के अधिक अनुरूप होगी, जिससे तेज अनुमोदन संभव होंगे और वैश्विक हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ेगा।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पीएलआई और थोक दवा (बल्क ड्रग) पार्क योजनाओं के सहारे सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) और मुख्य आरंभिक सामग्रियों (केएसएम) के स्थानीय उत्पादन में तेज़ी से प्रगति हुई है। इससे देश में दवाओं की कीमतें घटाने में मदद मिली है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम कीमतों में से एक है और इसके कारण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत किफायती बनी रहती है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ के मिशन बायोफार्मा निर्माण शक्ति की घोषणा इस दिशा में एक निर्णायक कदम को रेखांकित करती है। यह अगले 8 से 10 वर्षों में भारत को बायोफार्मा नवाचार और उच्च मूल्य वाली चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक केन्द्र बनाने के देश के संकल्प का संकेत देती है। यह विज़न गहरी वैज्ञानिक क्षमताओं के निर्माण, नवाचार-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और भारत को अगली पीढ़ी की दवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने में सक्षम बनाने पर आधारित होगा

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है, जिसके तहत 19,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। कैंसर और दुर्लभ रोगों की दवाओं जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं पर सीमा-शुल्क को सुव्यवस्थित करने जैसे पूरक उपाय जीवन रक्षक उपचारों तक पहुंच को और सुलभ बना रहे हैं। जैसे-जैसे उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाएं अधिक व्यापक होंगी, किफायती दर और समान पहुंच सुनिश्चित करना केंद्रीय नीति की प्राथमिकता बनी रहेगी।

जैसे-जैसे उद्योग विकसित हो रहा है, भारत का उद्देश्य न केवल स्थापित बाजारों में बल्कि उभरते क्षेत्रों में, विशेष रूप से नवाचार-संचालित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। सुधार, इस बदलाव के केंद्र में हैं। नियामक समन्वय, अनुमोदन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और तेजी से मंजूरी जैसे प्रयास व्यापार करने में आसानी को बढ़ा रहे हैं। गुणवत्ता मानकों और नियामक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने से भारतीय औषधि उत्पादों पर वैश्विक विश्वास की निरंतरता सुनिश्चित होती है। हालांकि, आरएंडडी निवेश बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसका समाधान करने के लिए, सार्वजनिक-निजी सहयोग को मजबूती देना आवश्यक होगा, ताकि दीर्घकालिक नवाचार को बनाए रहा जा सके।

नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति और बाजार का आपसी समन्वय; औषधि क्षेत्र के लिए विकास का एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है। भारत का घरेलू बाजार, जिसका मूल्य पहले से ही 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, निरंतर विस्तार के लिए तैयार है। अगले दशक में भारत न केवल जेनेरिक दवाओं में एक अग्रणी देश के रूप में, बल्कि नवोन्मेषी दवाओं, किण्वन-आधारित उत्पादों और अगली पीढ़ी की चिकित्सा-सेवाओं में भी एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरने के लिए बेहतर स्थिति में है।

निष्कर्ष के तौर पर भारत का औषधि क्षेत्र नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो नवाचार, सुदृढ़ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा द्वारा परिभाषित होता है। बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम जैसी पहलों, नैदानिक अवसंरचना के विस्तार और लक्षित निर्माण प्रोत्साहनों के समर्थन से भारत धीरे-धीरे मात्रा-संचालित जेनेरिक दवा केंद्र से उच्च-मूल्य वाले बायोफार्मा नवाचार अग्रणी देश की ओर आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में भारत की भूमिका को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न 'विकसित भारत 2047' के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। ■

श्रद्धांजलि

भाजपा के वरिष्ठ नेता बलबीर पुंज नहीं रहे

श्री बलबीर पुंज (1949–2026) एक अनुभवी पत्रकार थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो बार राज्यसभा सांसद रहे। एक प्रमुख वैचारिक आवाज़ के तौर पर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (2013) और पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश (2000–2006) और ओडिशा (2008–2014) से उच्च सदन (राज्यसभा) का प्रतिनिधित्व किया। उनका निधन 18 अप्रैल, 2026 को हुआ। वे 77 वर्ष के थे। श्री पुंज भाजपा के बौद्धिक एवं नीति-निर्माण से जुड़े रहे। उन्होंने उच्च सदन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजनीति में आने से पहले श्री पुंज ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशिष्ट करियर बनाया था। उन्होंने अपने पेशेवर सफर की शुरुआत 1971 में 'द मदरलैंड' नामक एक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ की थी। वे 1974 में 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' से जुड़े। उन्होंने 1996 तक, यानी दो दशकों से भी अधिक समय तक 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में काम किया। वे अपने सटीक विश्लेषण और टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। बाद में, उन्होंने मई, 1996 से मार्च, 2000 तक 'द ऑब्ज़र्वर ऑफ़ बिज़नेस एंड पॉलिटिक्स' के कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया।

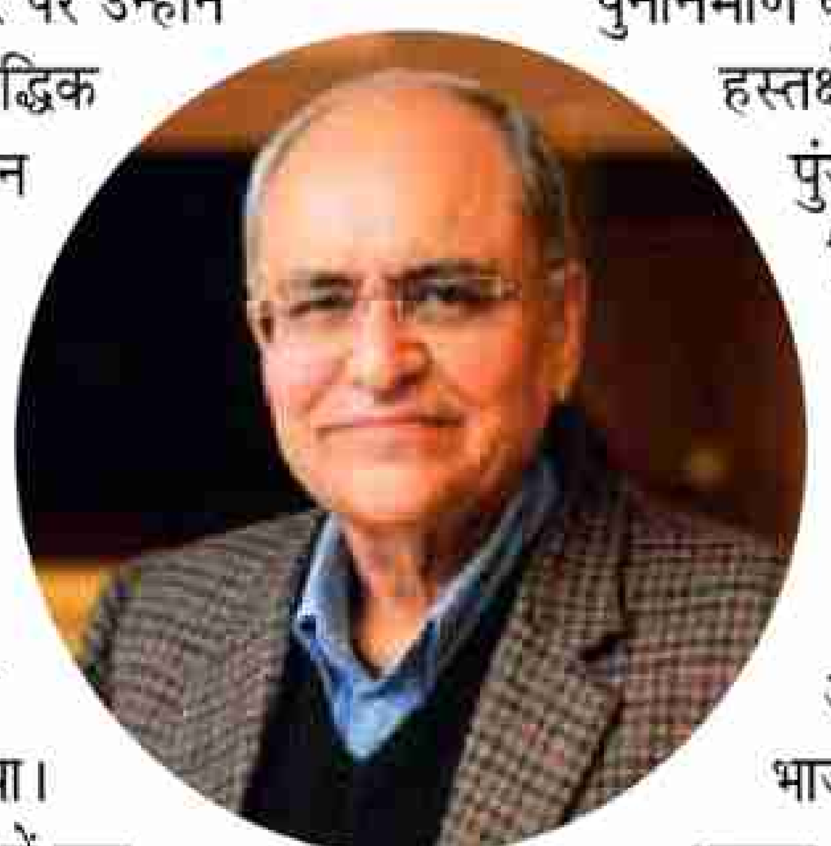

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पुंज के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री बलबीर पुंज जी एक प्रखर लेखक, विचारक और बुद्धिजीवी थे। उन्होंने मीडिया जगत में अपना समृद्ध योगदान दिया। उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, जो राष्ट्र-पुनर्निर्माण के प्रति उनके गहरे जुनून को दर्शाते थे। संसद में उनके हस्तक्षेप तथ्यों और सिद्धांतों से परिपूर्ण होते थे। श्री बलबीर पुंज जी ने भाजपा को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया, विशेष रूप से छात्रों, पेशेवरों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों के बीच। वे गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के प्रभारी रहे। उन दिनों हुई हमारी मुलाकातों की यादें आज भी ताजा हैं। उनके निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने कहा, "वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद बलबीर पुंज जी के निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है। सार्वजनिक जीवन में उनकी स्पष्ट वैचारिक दृष्टि, राष्ट्रहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपने लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार तथा समर्थकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें।" एक लेखक और स्तंभकार के रूप में वे अपने अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे और हिंदी तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में व्यापक रूप से लेखन कार्य करते रहे। उनके निधन से हमने एक अनुभवी पत्रकार, विचारक और राजनैतिक हस्ती को खो दिया है। ■

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती (14 अप्रैल) पर विशेष

बाबासाहेब के विचार, नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व और 'विकसित भारत' का संकल्प

लाल सिंह आर्य

राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा

बाबासाहेब का सबसे बड़ा सपना था— एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति जाति, वर्ग, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन और समाज का मूल सिद्धांत बनाने का प्रयास किया

संविधान शिल्पी भारत रत्न श्रद्धेय बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 136 वीं जयंती केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। यह वह दिन है, जब हम उस महापुरुष को स्मरण करते हैं, जिन्होंने सदियों की सामाजिक विषमता को चुनौती दी और एक ऐसे भारत की नींव रखी, जहां न्याय, समानता और गरिमा प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार हो। बाबासाहेब का जीवन संघर्ष, ज्ञान और संकल्प का अद्वितीय उदाहरण है— एक ऐसा जीवन, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और आत्मसम्मान की मशाल को कभी बुझने नहीं दिया।

डॉ. अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक बड़े अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ विधिवेत्ता, महान समाज सुधारक और दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता थे। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझा था कि यदि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं होगी; इसके साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करना होगा। यही कारण है कि उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी समान अवसर और अधिकार प्रदान करते हैं।

उनकी दूरदर्शिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू था— मजबूत संस्थाओं का निर्माण। बाबासाहेब का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति उसकी संस्थागत संरचना पर निर्भर करती है। वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, रोजगार कार्यालयों और श्रम नीतियों की जो बुनियाद उन्होंने रखी, वह आज भी भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। उनकी सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार किया।

इतना ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉ. अंबेडकर की डॉक्टरेट थीसिस ने भारत में वित्त आयोग की स्थापना की नींव रखी और उनके विचारों ने 1934 के आरबीआई अधिनियम के निर्माण को दिशा दी। उन्होंने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध और सोन नदी परियोजना जैसे बड़े बुनियादी ढांचों के विकास को प्राथमिकता दी, यह योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे केवल सामाजिक न्याय के ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के भी अग्रदूत थे। आज जब भारत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, तब यह स्पष्ट होता है कि हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी दिशा बाबासाहेब ने दशकों पहले तय की थी।

बाबासाहेब का सबसे बड़ा सपना था— एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति जाति, वर्ग, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन और समाज का मूल सिद्धांत बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है, जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी सुनिश्चित हो।

बाबासाहेब का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने समाज के वंचित, शोषित और

पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। उनका संघर्ष केवल अधिकारों के लिए नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान के लिए था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना और दलितों तथा वंचितों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उनका यह विश्वास था कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता।

आज जब हम वर्तमान भारत की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी परिकल्पना बाबासाहेब ने की थी। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली का आधार बन चुका है। अंत्योदय की भावना के साथ सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास का लाभ समाज के

आज का भारत बाबासाहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

मोदी सरकार ने आर्थिक समावेशन के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वे बाबासाहेब के आर्थिक चिंतन का जीवंत उदाहरण हैं। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, आधार और मोबाइल के साथ जोड़कर उन्हें सीधे लाभ पहुंचाया गया। डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूपीआई और भीम ऐप ने आम नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और शोषण और भ्रष्टाचार से बचाया है। यह सब उस सोच का विस्तार है, जिसमें बाबासाहेब आर्थिक सशक्तीकरण को सामाजिक मुक्ति का आधार मानते थे।

इसके साथ ही, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, वे भी उल्लेखनीय हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी योजनाएं देश को नई गति प्रदान कर रही हैं। यह सब केवल विकास परियोजनाएं नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं, जो बाबासाहेब के आर्थिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

जहां आज का भारत बाबासाहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे। उन्हें चुनावों में हराने के प्रयास हुए, संसद में उनकी उपेक्षा की गई और उनके विचारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कांग्रेस ने बाबासाहेब के जीवित और मरने के बाद राजनैतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करने के लिए एक बार नहीं, बहुत बार प्रयास किए।

इतना ही नहीं, बाबासाहेब को उनके जीवनकाल में 'भारत रत्न' से भी वंचित रखा गया और उनकी स्मृति से जुड़े स्थलों की उपेक्षा की गई। यह एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। वर्षों तक उनके योगदान को सीमित रखने का प्रयास किया गया, जिससे नई पीढ़ी उनके वास्तविक महत्व से परिचित नहीं हो सकी।

इसके विपरीत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बाबासाहेब को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय सम्मान दिलाने का कार्य किया है। पंचतीर्थ का निर्माण, लंदन स्थित उनके निवास को अंतरराष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित करना, संविधान दिवस की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र में उनकी जयंती का आयोजन— ये सभी पहल इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार उनके विचारों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून को सख्त बनाना तथा आरक्षण को आगे बढ़ाना— ये सभी निर्णय बाबासाहेब के उस सपने को साकार करते हैं, जिसमें हर वर्ग को समान अवसर मिले।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बाबासाहेब महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे थे। आज महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे उनके विचारों का ही विस्तार हैं।

आज भारत 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह वह भारत है, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, जहां विकास समावेशी होगा और जहां राष्ट्र आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मिशन 2047 अंतर्गत भारत सरकार ने 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें डॉ. अंबेडकर का आर्थिक चिंतन और उनके विचारों में समानता अर्थात समान अवसरों की उपलब्धता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता तीन एसे स्तंभ है जिन पर विकसित भारत खड़ा हो सकता है यानी सशक्त समाज और समृद्ध भारत! बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर जी का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि यदि सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय साथ-साथ चले तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बन सकता है। उनका सपना आज भी हमारे मिशन 2047 के लिए प्रेरणास्रोत है।

अंततः बाबासाहेब का सपना केवल सरकारों के प्रयासों से नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही साकार होगा। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

आज का भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है—एक ऐसा भारत, जो अपने अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह यात्रा केवल विकास की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय गौरव की भी है।

यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महान युगपुरुष को, जिसने हमें समानता, न्याय और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया। ■

प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया क्योंकि भाजपा ने लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाई है।

श्री हिमंता बिस्वा सरमा के एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही, #विकसित असम की ओर यात्रा जारी है।

RNI Regd. No. :- HPHIN/2015/74807 | Prepayment in Postage
Postal Regd. No. :- HP/118/SML (2024-26)
Date of Posting :- 2 June 2026 | Date of Publication :- 26 May 2026
Posted At - Shimla RMS, SHIMLA-4

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल कविंदर गुप्ता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं संवैधानिक मार्यादाओं के गंभीर उल्लंघन, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, जनादेश को कमजोर करने तथा सत्ता के दुरुपयोग के संबंध में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। साथ ही महामहिम राज्यपाल से इन विषयों पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

दीप कमल संदेश
दीपकमल भवन, टॉप फ्लोर, कामनानगर
चक्कर, शिमला–5
e-mail: deepkamalsandesh@gmail.com

प्रतिष्ठा में
....
....
....